

निदेशकों की रिपोर्ट

I. आर्थिक परिदृश्य एवं बैंकिंग परिवेश

विश्व का आर्थिक परिदृश्य

विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 3.6% थी। वर्ष 2019 में यह घटकर 2.9% रह गई। क्षेत्रीय स्तर पर वृद्धि दर में गिरावट मुख्यतया भारत, रूस और मैक्सिको की अर्थव्यवस्था में धीमेपन के कारण आई। कुल मिलाकर सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 3.7% रही। चीन के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2019 में 6.1% रही। यह वर्ष 1990 के बाद से सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध और बृहद अर्थव्यवस्था में धीमेपन के कारण ऐसा हुआ। भारत में भी आर्थिक वृद्धि दर में धीमापन दिखाई दिया। इसकी वजह निवेशों में गिरावट और धीमी औद्योगिक वृद्धि दर है।

इस दौरान विकसित देशों की वृद्धि दर 1.7% रही। कमजोर निर्यात मांग के चलते यूरो क्षेत्र की वृद्धि दर सुस्त रही। जर्मनी में विनिर्माण की गति उत्साहहीन रही, जबकि इटली में आर्थिक गतिविधियाँ विदेशों में अस्थिर परिस्थितियों और देश में नीतिगत अनिश्चितता के कारण प्रभावित रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी धीमापन देखा गया, क्योंकि कर कटौतियों से भी मदद नहीं मिली।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों में दरार और ब्रेक्सिट की अनिश्चितता के कारण वर्ष 2019 में पूरे विश्व के व्यापारिक निर्यातों को धक्का लगा। कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन से इस वर्ष व्यापार की गति बहुत ज्यादा प्रभावित होने के चलते कम से कम वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों में व्यापार गतिविधि (वस्तु एवं सेवा दोनों) कमजोर रहने की संभावना है।

जहां तक वित्तीय स्थिरता का प्रश्न है, बढ़ते कॉरपोरेट ऋण भार, संस्थागत निवेशकों के पास अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाली एवं गैर-नकद आस्तियों की अत्यधिक उपलब्धता और अनेक देशों की विदेशी उधारियों पर बढ़ती निर्भरता से सारा विश्व पहले से ही जूझ रहा था। कोविड महामारी ने वित्तीय स्थिरता की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। आस्तियों के घटते मूल्य एवं बाजार में अस्थिरता भी स्थिति को और विकट बना रही है।

आईएमएफ के अनुमान के अनुसार कोविड 19 के प्रकोप के कारण वर्ष 2020 में पूरे विश्व की आर्थिक वृद्धि दर नीची और जीडीपी वृद्धि दर -3.0% रहने की उम्मीद है। वृद्धि दर के आँकड़ों की ऐसी अनिश्चितता इसके पहले कभी नहीं देखी गई। परिवर्तनों का रुख सकारात्मक या नकारात्मक कैसा रहेगा, यह विभिन्न सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर निर्भर करेगा।

भारत का आर्थिक परिदृश्य

कोविड-19 महामारी फैलने से पहले भी भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020 में सामान्य होने की आशा की जा रही थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थानीय एवं वैश्विक मांग के धीमेपन और संबंधित क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रही थी। अनंतिम आकलनों के अनुसार समग्र सकल देशी उत्पाद संवृद्धि वित्त वर्ष 2019 के 6.1% की तुलना में घटकर वित्त वर्ष 2020 में 4.2% रही।

औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे अग्रिम आकलनों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में जीवीए वृद्धि दर घटकर 0.9% रह गई, जो एक वर्ष पहले 4.9% थी। विनिर्माण क्षेत्र में आई गिरावट ने देश-विदेश में कमजोर मांग के कारण उत्पन्न धीमेपन को और गहरा किया। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर ऊँची रही, पर बिजली सृजन एवं निर्माण गतिविधि कमजोर रही।

यात्रा, पर्यटन और संचार सेवाओं की वृद्धि दर घट जाने के कारण सेवा क्षेत्र जीवीए की वृद्धि दर भी वित्त वर्ष 2019 के 7.7% के स्तर से घटकर वित्त वर्ष 2020 में 5.5% पर आ गई। सरकारी व्यय की वृद्धि दर में भी कमी आई।

केवल कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों की वृद्धि दर ही वित्त वर्ष 2020 में 4% पर पहुँच पाई, जो वर्ष 2019 में 2.4% थी। वर्ष 2019-20 के लिए फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों में खरीफ और रबी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर को क्रमशः 1.7% और 5.6% प्रतिशत रखा गया है।

वित्त वर्ष 2020 के दौरान माल के निर्यात और आयात में कमी विश्व व्यापार के साथ-साथ वैश्विक मांग में लंबे समय तक धीमापन रहने का संकेत है। भारत के माल निर्यात (वर्षानुवर्ष) में वित्त वर्ष 2019 के 8.75% की वृद्धि दर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 4.8% की कमी आई, जबकि आयातों में वित्त वर्ष 2019 की 10.42% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में वृद्धि दर घटकर 9.1% रह गई। परंतु आयात में बड़ी गिरावट से विदेशी मुद्रा की स्थिति में मजबूती आई और चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2019 के अप्रैल-दिसंबर के 2.6% से घटकर वित्त वर्ष 2020 के अप्रैल-दिसंबर में जीडीपी का 1.0% रह गया।

चीजों के मूल्यों का जहां तक संबंध है, वित्त वर्ष 2020 के प्रथमार्ध तक लक्ष्य से कम मुद्रास्फीति के आँकड़ों से उत्पन्न अनुकूल स्थितियों पर द्वितीयार्ध में सब्जियों के दाम बढ़ने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। असामान्य रूप से दक्षिण पश्चिमी वर्षा बढ़ने और बेमौसमी वर्षा से खरीफ के द्वितीयार्ध में काटी गई फसल नष्ट हुई और प्याज के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ईंधन के मूल्य भी पाँच महीनों की अवधि से

निकलकर दिसंबर 2019 में सकारात्मक स्थिति में आ गए और उसके बाद तेजी से बढ़े। इन कारणों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ऊपर रहा और औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2019 के 3.43% की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 4.77% रही।

वर्ष 2019-20 के दौरान (i) रबी की भरपूर फसल एवं उच्चतर खाद्यान्न मूल्यों के कारण कोविड-19 महामारी से पहले ही वित्त वर्ष 2021 की वृद्धि दर का परिदृश्य ऊपर की ओर था, जिससे ग्रामीण मांग को मजबूत करने की अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न हुईं, (ii) खपत और निवेश मांग दोनों के अनुकूल प्रभाव के चलते नीतिगत दरों में कटौती का लाभ बैंक ऋण दरों में आगे देने की स्थिति में सुधार हुआ और (iii) जीएसटी दरों में कमी, सितंबर 19 में कॉरपोरेट कर दर में कटौती और घरेलू मांग को अधिकतर बढ़ाने के लिए ग्रामीण और बुनियादी ढाँचे के खर्च को बढ़ावा देने के उपाय करने से भी अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न हुईं। मौसम के प्रारंभिक अनुमानों में ला नीना की स्थितियों के कारण इस वर्ष मानसून के 'सामान्य से ऊपर' रहने के संकेत देने से भी विकास के परिदृश्य को बल मिला।

परंतु कोविड-19 महामारी ने इस परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव ला दिया है। वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी के गर्त में चले जाने की उम्मीद है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से आई कमी और इस कमी के निरंतर बने रहने से देश की व्यापार की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन लाभ की इस स्थिति से शटडाउन और विदेश में मांग की कमी होने वाले नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद नहीं है।

आने वाले समय में मुद्रास्फीति की स्थिति में तभी सुधार हो पाएगा यदि सब्जियों के दाम बढ़ने की रफ्तार धीमी हो, अन्य खाद्यान्न मूल्यों पर मुद्रास्फीति के दबाव कम हों, मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रमुख कारणों से लागत बढ़ने और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी का प्रकोप में कमी आए।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निर्यात की आगे की स्थिति पर असर हो सकता है। वित्त वर्ष 2021 का पहला महीना वर्षानुवर्ष आधार पर डॉलर में किए जाने वाले निर्यातों में 61% कमी के कारण खराब रहा और यह महामारी भविष्य के विकास के लिए अच्छा शकून नहीं है। पर तेल की कीमतों में कमी से आयात खर्च में कमी आ सकती है, जिससे टिकाऊ चालू खाता शेष बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

बैंकिंग परिवेश

वर्ष के दौरान कुल जमा वृद्धि वित्त वर्ष 20 में 7.9% पर बंद होने से पहले 9% से 11% के बीच रही। कम वृद्धि पिछले वर्ष के अत्यधिक आधार एवं कोविड संकट के कारण रही। धीमी गति एवं गैर-अनुकूल बेस प्रभाव के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान ऋण का कुल व्यापार भी मंद रहा, जिससे ऋण संवृद्धि वर्ष 2018-19 के 13.3% की तुलना में 6.1% पर आधे से कम रही। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही की ऋण संवृद्धि में मौसमी गिरावट पिछले वर्ष से भी अधिक रही, जबकि वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में कुल व्यापार पिछले दो वर्षों की तदनुसूची तिमाहियों की तुलना में मंद रहा। ऋण संवृद्धि में मंदी सभी बैंक समूहों विशेषकर निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच फैला रहा। चौथी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋणों में कुछ वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं विदेश बैंकों की ऋण संवृद्धि कम रही। ऋण का कुल व्यापार मंद रहने और गैर-एसएलआर निवेश घट जाने के कारण बैंकों ने अपने एसएलआर संविभाग को बढ़ाया। बैंकों ने वित्त वर्ष 2019 में निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 6.3% की तुलना में निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के लगभग 7.5% का अतिरिक्त एसएलआर अपने पास रखा।

मार्च 2020 के क्षेत्र-वार ऋण आंकड़ों से केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धिशील ऋण बढ़ने का संकेत मिलता है और अन्य सभी क्षेत्रों ने कमी को दर्शाया है। वित्त वर्ष 2020 में उद्योग को दिए गए ऋणों में 1.4% (वित्त वर्ष 2019 में 6.9%) तथा सेवाओं में 8.5% (वित्त वर्ष 2019 में 17.8%) की गिरावट आई। वैयक्तिक ऋणों में वित्त वर्ष 2019 के 16.4% की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 15.7% की मामूली कमी आई, जबकि कार्यशील पूंजी सीमा में वृद्धि के रूप में बैंकों से संवर्धित सहायता मिलने के चलते मध्यम एवं लघु उद्यम एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए गए ऋणों में पर्याप्त वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2020 में मौद्रिक नीतिगत दरों में सुधार का लाभ बैंकों की मीयादी जमा राशियों एवं ऋण ब्याज दरों में आगे देने से वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान बैंकों की जमा एवं ऋण ब्याज दरों का अधिक लाभ देने से पता चलता है कि पिछली दर कटौतियों (फरवरी-सितंबर 2019 के दौरान 110 आधार अंक) एवं चयनित क्षेत्रों यथा रिटेल ऋण और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को नई स्थिर दर वाले नए ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बाह्य बेंचमार्क प्रणाली शुरू किए जाने के कम असर को दर्शाता है। साथ ही आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिपो दर में कटौती का अनुपालन करते समय मीयादी जमा

दरों में कटौती को न्यूनतम बनाने का प्रयास किया है, ताकि जमाकर्ता पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों के लिए जमा दर कटौतियाँ एमसीएलआर कटौतियों की तुलना में ज्यादा रही हैं।

भावी परिदृश्य

पिछला वित्त वर्ष बैंकों की दृष्टि से मिश्रित फलदायक रहा। वित्त वर्ष के प्रथमार्ध में तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में अच्छी प्रगति हुई। सामान्य बजट से संवृद्धि को बल मिला। परंतु निजी खपत में धीमेपन की पृष्ठभूमि में, भारतीय निजी बैंकिंग में वित्तीय अस्थिरता एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में अलाभकारी आस्तियों के समाधान में देरी के कारण तीसरी तिमाही में परिदृश्य में बदलाव देखने को मिला।

चौथी तिमाही की शुरुआत के साथ चीन के मैदानी भाग में तथा उसके बाद विश्व में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने के कारण वैश्विक विकास का परिदृश्य काफी बदल गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल में घोषित की जानी वाली मौद्रिक नीति को मार्च महीने में ही घोषित कर दिया और संवृद्धि का कोई पूर्वानुमान भी नहीं दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी शुरू किए।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर कोविड-19 के प्रकोप का प्रभाव नाटकीय और गंभीर रहा है। तेल के दामों में 70% से भी अधिक गिरावट के कारण पण्यों के दामों में तेजी से अवस्फीति देखी गई। भारत सहित उभरते बाजारों में ईक्विटी बाजार भी तेजी से बढ़े। वित्त वर्ष 2021 में सकारात्मक संवृद्धि की तुलना में भारी नकारात्मक संवृद्धि के साथ यद्यपि भारत की जीडीपी संवृद्धि का पूर्वानुमान काफी अलग है, लॉकडाउन उपायों के कारण मांग न होने से समाज के गरीब वर्गों की आय का पर्याप्त नुकसान हुआ है।

इस संदर्भ में, बैंक व्यवसाय के भावी परिदृश्य पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करने की जरूरत है। परिवहन जैसे क्षेत्रों में मांग न होने के कारण उत्पादन में नुकसान का अन्य क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बिक्री राशियों की प्राप्ति में देरी के चलते कार्यशील पूंजी अवधि बढ़ने की वजह से कार्यशील पूंजी ऋण की मांग बढ़ी है और उनके निचली श्रेणी में आने की संभावना बढ़ गई है। आय में नुकसान का प्रतिकूल असर भविष्य में बैंक की जमा राशि जुटाने की रणनीति पर पड़ सकता है।

परंतु, कोविड-19 महामारी के कारण बैंकों के लिए अवसर भी खुल गए हैं। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्व्यवस्थित किए जाने से भारत को वैश्विक मांग की पूर्ति करने में स्वयं को विनिर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाने का अद्वितीय अवसर भी उपलब्ध हुआ है। जिस सीमा तक राज्य सरकारें चीन से किए जाने वाले व्यवसायों को सुरक्षित रूप से दूसरे देशों को भारत में लाने में जितनी समर्थ होती हैं, बैंकों को अपने व्यवसाय को विस्तारित करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कोविड-19 के जवाब में डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाए जाना बैंकों की दृष्टि से अच्छा शगुन है, क्योंकि इससे बैंकों के डिजिटल उत्पाद भी तेजी से बढ़ेंगे।

संक्षेप में बैंक के व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था का भावी परिदृश्य वाहरस को पूर्ण रूप से नष्ट करने और सामान्य स्थिति बहाल होने पर निर्भर करेगा। हाल ही में दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज, उसकी प्राथमिकताओं एवं निधीयन कार्यनीति से यह तय होगा कि किस तरह बैंक कोविड के बाद के परिदृश्य में काम करेंगे। बैंक को कारोबार के नए परिचालन परिवेश को बेहतर रूप से अपनाने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे, उसके जोखिम निर्धारण के आंतरिक मॉडलों एवं पूंजी आयोजना तथा व्यवसाय कार्यविधियों की पुनः समीक्षा करनी होगी।